

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में, 1-आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3-संभागीय खाद्य नियंत्रक
गढ़वाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

2- जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर/हरिद्वार/
चम्पावत/देहरादून/पौड़ी/
नैनीताल।

4- महाप्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक ०३ ^{दिसम्बर} नवम्बर, 2007.

विषय:-खरीफ-खरीद सत्र 2007-08 में विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत लेवी चावल का उद्ग्रहण और क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खरीफ-खरीद सत्र 2007-08 लेवी चावल हेतु निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपशान्त अधिसूचना संख्या 267/०७-XIX-2/22 खाद्य/०७ दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 में निम्नलिखित आशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. उक्त अधिसूचना के विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत चावल का उद्ग्रहण और क्रय संबंधी बिन्दु-1 के उप बिन्दु 1.1 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित "लेवी योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-12-2007 तक अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व मिलर्स द्वारा धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करने के उपरान्त ही अन्य प्रदेशों से मिलर्स द्वारा क्रय किये गये धान पर लेवी लेने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा" के स्थान पर "अन्य राज्यों से लिये गये धान पर लेवी ली जायेगी", पढ़ा जायेगा।

2. अधिसूचना के बिन्दु 3 के लेवी की दर के प्रस्तर 3.1 को निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

"चावल की खरीद चावल मिलों पर लेवी लगाकर की जायेगी। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लेवी की दर 80 प्रतिशत रहेगी तथा यह ऐच्छिक रहेगी।"

3. उत्तराखण्ड राईस मिलर्स संघ द्वारा शासन स्तर पर मार्ग हानि से डेढ़ गुनी कटौती को समाप्त किए जाने सम्बन्धी मांग के क्रम में स्पष्ट करना है कि उक्त अधिसूचना के बिन्दु 9.5 पर यद्यपि स्थिति स्पष्ट की गयी है। इस सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट करना है कि चूँकि राईस मिलर परिवहन ठेकेदार का कार्य स्वयं करते हैं, ऐसी स्थिति में जितनी लेवी चावल की मात्रा मिलर द्वारा संग्रहण डिपो (भारतीय खाद्य निगम/स्टेटपूल) पर प्राप्त करायी जायेगी उतनी ही लेवी चावल की मात्रा का भुगतान किया जायेगा।

4. अधिसूचना के चावल की खरीद के लिए लाट का निर्धारण सम्बन्धी बिन्दु 13 में की गयी व्यवस्था "समस्त केन्द्रों पर एक समान यूनिफॉर्म मात्रा 50 कि०ग्रा० भरती वाले बोरी में 100 कुन्तल/200 कट्टों की लाटों में चावल की खरीद की जायेगी" के स्थान पर "समस्त केन्द्रों पर एक समान यूनिफॉर्म मात्रा 50 कि०ग्रा० भरती वाले बोरी में 150 कुन्तल/300 कट्टों की लाटों में

चावल की खरीद की जायेगी, तथा लेवी चावल का संचरण परिवहन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों/नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा" पढ़ा जाये।

5. अधिसूचना के क्रय केन्द्र से संग्रह ऐजेन्सी तक चावल का परिवहन सम्बन्धी बिन्दु-16 में मिल गोदाम से संग्रह ऐजेन्सी के इंगित डिपो तक चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा जिसके लिये परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा खरीफ-खरीद वर्ष 2006-2007 हेतु स्वीकृत परिवहन दरों पर किया जायेगा के स्थान पर "मिल गोदाम से संग्रह ऐजेन्सी के इंगित डिपो तक चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा जिसके लिये परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा खरीफ-खरीद वर्ष 2007-2008 हेतु स्वीकृत परिवहन दरों पर किया जायेगा" पढ़ा जायेगा।

6. अधिसूचना के चावल के भरे बोरे पर स्टैंसिलिंग, कोडिफिकेशन और लाट संख्याकन सम्बन्धी बिन्दु 19.1 के प्रस्तर दो को निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

"चावल मिलर द्वारा बोरे पर कोड नम्बर आदि अंकित न किए जाने पर उक्त लेवी चावल की डिलीवरी स्वीकार नहीं की जायेगी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.11.06 में दिए गए निर्देशानुसार कोड संख्या लाल रंग से अंकित की जाये तथा स्टैंसिलिंग नीले रंग से अंकित की जायेगी। बोरे भरने के पश्चात् मुंह के हिस्से पर सिलाई "लाल रंग" द्वारा की जायेगी तथा बोरे के बीच में लम्बाई पर एक नीले रंग की अकेली स्ट्रिप होगी"।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आशिक संशोधन संबंधी सभी बिन्दुओं का अनुपालन तदनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(डा० रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या 8870-रा(1)/07-XIX-2/22 खाद्य/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मंडल पौड़ी/कुमार्यू मण्डल नैनीताल।
2. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सी०डब्ल्यू०सी०/एस०डब्ल्यू०सी०, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ सभागीय वित्त अधिकारी, गढ़वाल संभाग, देहरादून/कुमार्यू संभाग, हल्द्वानी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी लि०, देहरादून।
7. निजी सचिव, खाद्य मंत्री को मा० खाद्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।